बाजार गतिशीलता को समझना

संवहनीयता की सफलता हेतु जिम्मेदारीपूर्ण प्रत्युत्तर

बैंकिंग उद्योग संरचना

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मोटे तौर पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है. अनुसूचित बैंकों को आगे वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में विभाजित किया गया है. वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक शामिल हैं. सहकारी बैंकों में शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियाँ शामिल हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है. भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आपके बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों में से एक है. वर्ष 2020 में विलय के पश्चात, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित किया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में इसकी स्थिति और सुदृढ़ हो गई. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, जिसमें नियमित बचत और ऋण, बीमा और निवेश सेवाओं जैसी अधिक जटिल खातों की जांच शामिल हैं. इसकी उपस्थिति केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि कई ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली हुई है, इस प्रकार यह ग्रामीण विकास का समर्थन प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मजबूत बना हुआ है और भारत के आर्थिक सुधार में योगदान दे रहा है. हमारी संतुलित ऋण वृद्धि और बेहतर संपत्ति गुणवत्ता लगातार विकसित हो रही बैंकिंग में हमारी अनुकूलन क्षमता को प्रमाणित करती है

बैंकिंग उद्योग गतिकी

वित्त वर्ष 2022-23 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण ट्रांसफॉरमेशन और लचीलेपन की अवधि है. मौद्रिक नीति समिति की नीतिगत बदलावों और चुनौतीपूर्ण वैश्विक वित्तीय स्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र ने सराहनीय अनुकूलनशीलता दर्शाई है. इस वर्ष आपके बैंकिंग उद्योग में इन बदलावों को देखा गया है, सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुदृढ़ ऋण वृद्धि, मध्यम गैर-निष्पादित ऋण और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ ये बदलाव देखने को मिले हैं. इसके अतिरिक्त, पॉलिसी रेपो दर में वृद्धि के बावजूद, आपका बैंकिंग उद्योग

वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच युनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थिर बना हुआ है और भारत के आर्थिक सुधार में योगदान दे रहा है. हमारी स्थिर ऋण वृध्दि और उन्नत सम्पत्ति गुणवत्ता लगातार विकसित हो रहे बैंकिंग उद्योग में हमारी अनुकूल क्षमता को प्रमाणित करती है.

खुदरा और थोक जमा दरों के परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करते हुए सशक्त जमा वृद्धि बनाए रखने में कामयाब रहा है. यह रुझान एक स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं, जो भारत की आर्थिक सुधार और वृद्धि का समर्थन करने में सक्षम है और आगामी वित्तीय वर्षों में और प्रगति के लिए तैयार है.

वर्ष 2022-23 में आरबीआई की मौद्रिक नीति में बदलाव: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुद्रास्फीति से निपटने और विकास का समर्थन करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया है. इसने मई, 2022 से फरवरी, 2023 तक पॉलिसी रेपो दर में 250 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है. इस कार्यनीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के साथ संरेखित करना तथा विकास के लिए एक स्थिर आर्थिक वातावरण प्रदान करना है.

मुद्रा बाजार प्रतिक्रियाएं और रेपो दर संचरण: वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में, विभिन्न परिपक्वताओं के लिए मुद्रा बाजार दरों में पॉलिसी रेपो दर में वृद्धि हुई, जो प्रचलित अधिशेष तरलता को दर्शाती है. इस विलोपन का प्रभाव भारित औसत कॉल मनी दर (डब्ल्यूएसीआर) में स्पष्ट था, जो रेपो दर के साथ संरेखित हुआ. इसके अलावा, ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था, आपके बैंकिंग सिस्टम में अधिशेष तरलता में कमी और जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि की निरंतरता के कारण, नीतिगत रेपो दर को बैंकों की ऋण और जमा दरों में स्थानांतरित करने की गति बढ़ गई है.

प्रतिकूल वैश्विक वित्तीय स्थिति में लचीलापन: वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में चुनौतीपूर्ण वैश्विक वित्तीय परिदृश्य के समक्ष, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लचीलेपन कार्यनिष्पादन रहा. इसने पर्याप्त पूंजी बफर और गैर-निष्पादित ऋणों का मध्यम स्तर बनाए रखा. बैंक उच्च शुद्ध ब्याज आय के माध्यम से अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में कामयाब रहे क्योंकि निवेश पोर्टफोलियो पर बढ़ती ब्याज दरों का प्रभाव सीमित रहा.

बैंक ऋण वृद्धि में तेजी: आर्थिक गतिविधियों में सुधार के प्रतिउत्तर में, बैंक ऋण वृद्धि, खासकर गैर-खाद्य क्षेत्र में तेजी देखी गई. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने सितंबर 2022 तक गैर-खाद्य ऋण वृद्धि में 16.7% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2022 के अंत में 9.7% थी. यह मजबूत ऋण वृद्धि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बनी रही, जो अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की मांग से प्रेरित थी.

क्षेत्र-वार ऋण विस्तार: वित्त वर्ष 2022-23 में, सभी प्रमुख क्षेत्रों में बैंक क्रेडिट में सुधार, ध्यान देने योग्य था. कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि का अनुभव हुआ, जिसका मुख्य कारण मानसून की अच्छी स्थिति और कृषि ऋण के लिए बढ़ा हुआ लक्ष्य था. बड़े उद्योगों और एमएसएमई खंड दोनों के योगदान के कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी ऋण वृद्धि में सुधार देखा गया. वर्ष के दौरान खुदरा ऋण, ऋण वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चालक बना रहा.

जमा राशि में वृद्धि और आस्ति गुणवत्ता सुधार: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी कुल जमा में तेजी से वृद्धि देखी, जो कि ब्याज दरों में काफी वृद्धि के कारण हुई. हालाँकि, यह जमा वृद्धि वर्ष के लिए ऋण वृद्धि से पिछड़ गई. आस्ति गुणवत्ता के मामले में, एससीबी ने समग्र गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात में गिरावट के साथ पर्याप्त सुधार दर्ज किया है.

बैंकों की उधार और जमा दरों का समायोजन: मई 2022 से पॉलिसी रेपो दर में बढ़ोतरी के प्रत्युत्तर में, 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बैंकों की जमा और उधार दरों में भी वृद्धि हुई. मजबूत ऋण वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिए खुदरा जमा राशि बढ़ाने के प्रयासों से, विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में, खुदरा जमा दरों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया.

बाजार गतिशीलता को समझना

संवहनीयता सफलता हेतु जिम्मेदारीपूर्ण प्रत्युत्तर

भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में बदलाव: फ्रेश जमा (खुदरा और थोक सहित) पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में मई 2022 से फरवरी 2023 तक 222 बीपीएस की वृद्धि देखी गई. प्रारंभ में, बैंकों ने थोक जमा जुटाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में नए खुदरा जमा दरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया. इस बदलाव के परिणामस्वरूप सावधि जमा दरों में समग्र वृद्धि हुई, जिससे जमाकर्ताओं की ओर से स्थिर निधियों की बढ़ती मांग उजागर हुई.

खतरा, जोखिम और चिंताएँ

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, अपने उल्लेखनीय विकास पथ और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अभिन्न भूमिका निभाने के साथ-साथ, डिजिटल रूप से प्रभावी और स्थिरता के प्रति जागरूक दुनिया में खतरें, जोखिमों और चिंताओं के एक अद्वितीय सम्मिश्रण का सामना कर रहा है.

1. **डिजिटल व्यवधान और साइबर सुरक्षा जोखिम:**

   विकास के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हुए, डिजिटल क्रांति एक दोधारी तलवार है. डेटा उल्लंघनों, फ़िशिंग और रैंसमवेयर हमलों जैसे साइबर खतरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है. डिजिटल बैंकिंग के विस्फोट ने अपराधियों के हमले की तीव्रता को बढ़ा दिया है जिसके कारण बैंकों को वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है.

2. **परिचालन जोखिम:**

   प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में वृद्धि के साथ, सिस्टम आउटरेज, आईटी विफलताओं, या लोग और प्रणाली जैसी आंतरिक प्रक्रियाओं में खराबी के कारण परिचालन जोखिम में वृद्धि हुई है.

3. **नियामक अनुपालन:**

   नियामक परिदृश्य और शर्तें तेजी से सख्त होते जा रहे हैं, जिससे धन शोधन निवारण (एएमएल) कानूनों से लेकर अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) प्रोटोकॉल सहित बैंकों को विभिन्न नियमों का पालन करना आवश्यक हो गया है. गैर-अनुपालन से महत्वपूर्ण वित्तीय दंड और प्रतिष्ठा की क्षति का सामना करना पड़ सकता है.

4. **आस्ति की गुणवत्ता और ऋण जोखिम**

   भारतीय बैंकों को मुख्य रूप से उच्च कॉर्पोरेट और कृषि क्षेत्र ऋण के कारण गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) संबंधी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों ने ऋण जोखिम की स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है.

5. **स्थिरता संबंधी चिंताएँ:**

   वैश्विक जलवायु परिवर्तन के समक्ष, बैंकों पर हितधारकों की ओर से अधिक स्थिर परिचालन में परिवर्तन करने और यह सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ रहा है कि उनके ऋण पोर्टफोलियो जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं के साथ संरेखित हों.

हम साइबर सुरक्षा उपायों को और आगे बढ़ाकर, डिजिटल क्षमताओं में सुधार और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर जोखिमों को सक्रिय रूप से कम करते हैं. हमारी बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन प्रणालियाँ आस्ति की गुणवत्ता की सुरक्षा करती हैं, जबकि स्थिरता पर हमारा ध्यान हमारे परिचालन में ईएसजी मानदंडों को शामिल करने से स्पष्ट होता है.

प्राथमिकता आधार पर संवहनीयता के साथ डिजिटल दुनिया में सफलता हेतु कार्यनीतियाँ

आपको बैंकिंग क्षेत्र के गतिशील परिदृश्य को पहचानकर और इन कार्यनीतियों को लागू करके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, कार्यनिष्पादन को अनुकूलित कर सकता है और डिजिटल और स्थिरता के प्रति जागरूक दुनिया में सफल हो सकता है. बहरहाल, इसके लिए तकनीकी अपनाने, नियामक को समझने, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन एवं नवाचार और अनुकूलनशीलता की संस्कृति द्वारा समर्थित स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के नाजुक संतुलन की आवश्यकता है. इसकी प्रमुख कार्यनीतियाँ निम्नानुसार होंगी:

संबंधित मुख्य विषय	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया	जीआरआई से संबंधित	अधिक जानकारी	स्ट्रेटजी आईकन
डिजिटल व्यवधान और साइबर सुरक्षा जोखिम	डेटा एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण और एआई-आधारित खतरे का पता लगाने जैसी उन्नत तकनीकों को लागू करके साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करें. नवीनतम साइबर खतरों से अपडेट रहने और सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा ऑडिट और कर्मचारी प्रशिक्षण आयोजित करें.	जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता और जीआरआई 419: सामाजिक आर्थिक अनुपालन	बौद्धिक पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 82	
परिचालन जोखिम	फिनटेक और बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाएं. उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप्स विकसित करें, वैयक्तिकृत सेवाओं के लिए एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स को अपनाएं, संचालन को सुव्यवस्थित करें और सुरक्षित लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करें.	जीआरआई 419: सामाजिक आर्थिक अनुपालन	बौद्धिक पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 82	
नियामक अनुपालन	नियामक जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए एक मजबूत अनुपालन रेगटेक सोल्यूशन को अपनाएं. अनुपालन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और विकसित नियमों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए रेगटेक समाधान अपनाएं	जीआरआई 419: सामाजिक आर्थिक अनुपालन	जोखिम ढांचा पर अध्याय पृष्ठ 91	
आस्ति गुणवत्ता एवं ऋण जोखिम	ऋण मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करें और ऋण देने के लिए समुचित सावधानी बरतें. संभावित एनपीए की पहचान करने और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उन्नत विश्लेषण में निवेश करें.	जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन	वित्तीय पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 62	
संवहनीयता चिंताएँ	ऋण संबंधी निर्णयों और परिचालन कार्यनीतियों में ईएसजी मानदंड शामिल करें. स्थायी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरित ऋण, हरित बंधक और हरित बांड जैसे हरित बैंकिंग उत्पाद पेश करें	जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन, जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव, और जीआरआई 300: पर्यावरणीय.	सामाजिक व संबंध पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 104; प्राकृतिक पूंजी, पृष्ठ 90; कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, पृष्ठ 198	